

डिजिटल डिवाइड का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. सन्तराम पाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी. जी. कॉलेज, बभनान, गोंडा (उ.प्र.)

Email: spal1190@gmail.com

Received: 06 August 2026 | Accepted: 20 August 2026 | Published: 30 August 2026

Abstract (सार)

डिजिटल डिवाइड से आशय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच, उपयोग और उसके लाभ उठाने की असमानता से है। प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य इस असमानता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण करना है तथा यह समझना है कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता किस प्रकार सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। शोध में यह पाया गया कि डिजिटल डिवाइड केवल तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि यह गहराई से सामाजिक असमानताओं से जुड़ी हुई है। समाज के उच्च वर्ग, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तथा शिक्षित जनसंख्या डिजिटल तकनीकों तक अधिक पहुँच रखते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र, निम्न आय वर्ग, महिलाएँ और हाशिए पर रहने वाले समुदाय इससे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड सामाजिक स्तरीकरण को और मजबूत करता है।

अध्ययन में यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा डिजिटल असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन व्यक्तियों के पास उच्च शिक्षा और डिजिटल साक्षरता होती है वे इंटरनेट और अन्य तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। इसके विपरीत, अशिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी डिजिटल बहिष्करण को बढ़ाती है। इसके अलावा, भाषा भी एक बाधा के रूप में सामने आती है क्योंकि अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेज़ी में उपलब्ध होती है जिससे स्थानीय भाषाओं के उपयोगकर्ता पीछे रह जाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र लैंगिक असमानता को भी रेखांकित करती है। कई समाजों में महिलाओं को तकनीकी संसाधनों तक कम पहुँच मिलती है जिससे उनका डिजिटल सशक्तिकरण बाधित होता है। यह स्थिति रोजगार, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में भी असमानता उत्पन्न करती है। आर्थिक दृष्टि से डिजिटल डिवाइड आय के अवसरों को भी प्रभावित करता है। जिन लोगों के पास डिजिटल साधनों की पहुँच है, वे ऑनलाइन शिक्षा, ई-व्यापार, और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं जबकि अन्य लोग इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड आर्थिक असमानता को और बढ़ा देता है।

शोध में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार और नीतिनिर्माताओं को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार, सस्ती डिजिटल सेवाएँ, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और स्थानीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही, निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। अंततः शोधपत्र से स्पष्ट होता है कि डिजिटल डिवाइड एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है जिसका समाधान केवल तकनीकी विकास से नहीं बल्कि समावेशी सामाजिक नीतियों और जागरूकता से संभव है। यदि इस असमानता को कम नहीं किया गया तो यह समाज में पहले से मौजूद विभाजनों को और गहरा कर सकती है। इसलिए डिजिटल समावेशन को सामाजिक न्याय और विकास के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाना चाहिए।

मुख्यशब्द: डिजिटल डिवाइड, सामाजिक असमानता, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल बहिष्करण, सामाजिक समावेशन।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण 'सूचना क्रांति' का युग कहा जाता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन और सामाजिक संपर्क इत्यादि को गहराई से प्रभावित किया है। इस परिवर्तन ने न केवल सूचना के प्रवाह को तीव्र किया है बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों को भी

व्यापक बनाया है। यद्यपि, यह तकनीकी प्रगति समान रूप से वितरित नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच डिजिटल संसाधनों की पहुँच, उपयोग और लाभ उठाने की क्षमता में गहरा अंतर मौजूद है। यही असमानता “डिजिटल डिवाइड” के रूप में जानी जाती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटल डिवाइड केवल तकनीकी संसाधनों की कमी का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं, जैसे- वर्ग, जाति, लिंग, शिक्षा और भौगोलिक स्थिति का विस्तार है। **मैनुअल कैसल्स**¹ के अनुसार, आधुनिक समाज “नेटवर्क सोसायटी” में परिवर्तित हो गया है जहाँ सूचना और नेटवर्क तक पहुँच ही शक्ति और अवसर का निर्धारक बन गई है। इसी प्रकार **जान वान डिज्क**² ने डिजिटल असमानता को सामाजिक असमानता का विस्तार बताया है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड के समाजशास्त्रीय आयामों का विश्लेषण करना है और यह समझना है कि यह किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को पुनः उत्पन्न करता है।

डिजिटल डिवाइड की अवधारणा

डिजिटल डिवाइड की अवधारणा सन 1990 के दशक में सामने आई जब यह स्पष्ट हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार असमान है। सामान्यतः यह उन व्यक्तियों, समूहों या क्षेत्रों के बीच अंतर को दर्शाता है जिनके पास डिजिटल संसाधनों तक पहुँच है और जिनके पास नहीं है। **पिप्पा नोरिस**³ के अनुसार- डिजिटल डिवाइड केवल तकनीकी पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक भागीदारी, सूचना तक पहुँच और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता को भी प्रभावित करता है। **जन वान डिज्क** के अनुसार यह बहु-स्तरीय दृष्टिकोण दर्शाता है कि केवल इंटरनेट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है; उसका प्रभावी उपयोग और उससे मिलने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभ भी महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल डिवाइड को तीन प्रमुख स्तरों में समझा जा सकता है: 1. Access Divide- इंटरनेट और उपकरणों तक पहुँच 2. Skill Divide- डिजिटल कौशल और उपयोग की क्षमता 3. Outcome Divide- डिजिटल उपयोग से प्राप्त लाभ।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

क) सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत

पियरे बोर्दियो⁴ ने समाज में असमानता को समझाने के लिए “पूँजी” की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी शामिल हैं। डिजिटल युग में, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल को एक नई “सांस्कृतिक पूंजी” के रूप में देखा जा सकता है। जिन व्यक्तियों के पास यह पूंजी होती है, वे बेहतर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसर प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शहरी और शिक्षित परिवार का छात्र ऑनलाइन कोर्स, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का छात्र बुनियादी मोबाइल उपयोग तक सीमित रह सकता है। इस प्रकार, डिजिटल कौशल सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है।

ख) नेटवर्क सोसायटी का सिद्धांत

मैनुअल कैसल्स के अनुसार, आधुनिक समाज “नेटवर्क” पर आधारित है। सूचना और संचार नेटवर्क से जुड़े लोग अधिक अवसरों का लाभ उठाते हैं, जबकि जो लोग इन नेटवर्क्स से बाहर हैं, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं। इस संदर्भ में डिजिटल डिवाइड, नेटवर्क तक पहुँच के असमान वितरण को दर्शाता है।

(ग) सेकंड-लेवल डिजिटल डिवाइड

एस्टर हरगिटार्ई⁵ ने डिजिटल डिवाइड के “दूसरे स्तर” पर ध्यान केंद्रित किया जो उपयोगकर्ता के कौशल और क्षमता से संबंधित है। उनके अनुसार, केवल इंटरनेट तक पहुँच होना पर्याप्त नहीं है; यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति उसका उपयोग कैसे करता है। उदाहरण: कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग शिक्षा और रोजगार के लिए करता है जबकि दूसरा व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए। इस प्रकार, कौशल का अंतर डिजिटल असमानता को और गहरा करता है।

डिजिटल डिवाइड के स्तर

डिजिटल डिवाइड के अनेक स्तर हैं, जैसे- क) पहुँच का विभाजन- यह डिजिटल डिवाइड का सबसे मूल स्तर है जिसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। ख) कौशल का विभाजन- यह स्तर डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता से संबंधित है। मार्क वार्सचौअर के अनुसार- डिजिटल समावेशन के लिए केवल उपकरण ही नहीं बल्कि कौशल भी आवश्यक है। ग) परिणाम का विभाजन-यह स्तर दर्शाता है कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक लाभ में परिवर्तित होता है। कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आय अर्जित करते हैं जबकि अन्य केवल मनोरंजन तक सीमित रहते हैं।

डिजिटल डिवाइड के कारक

डिजिटल डिवाइड के अनेक कारक भी हैं, जैसे- क) ग्रामीण-शहरी विभाजन-भारत में डिजिटल अवसंरचना असमान रूप से विकसित है। TRAI⁶ की रिपोर्ट के अनुसार- शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क और बिजली की समस्याएँ हैं। ख) लैंगिक असमानता- भारत में महिलाओं की डिजिटल पहुँच पुरुषों की तुलना में कम है। इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं: पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा की कमी, मोबाइल उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण आदि “डिजिटल पितृसत्ता” के उदाहरण हैं। ग) आर्थिक असमानता- गरीब परिवारों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा की लागत एक बड़ी बाधा है। अक्सर एक ही मोबाइल फोन पूरे परिवार द्वारा साझा किया जाता है जिससे उपयोग की सीमाएँ बढ़ जाती हैं। घ) भाषाई बाधा- भारत में अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है जिससे स्थानीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को कठिनाई होती है। IMAI⁷ एवं Kantar की रिपोर्ट के अनुसार- भारतीय भाषाओं में सामग्री की कमी डिजिटल बहिष्करण को बढ़ाती है।

केसस्टडी

केरल बनाम बिहार: केरल और बिहार के बीच डिजिटल विकास में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। केरल उच्च साक्षरता दर, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल शिक्षा का व्यापक उपयोगवाला राज्य है वहीं बिहार कम डिजिटल साक्षरता, सीमित इंटरनेट पहुँच, ऑनलाइन शिक्षा में बाधाएँ युक्त राज्य है। TRAI के अनुसार यह तुलना दर्शाती है कि डिजिटल डिवाइड केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और नीतिगत कारकों का परिणाम है।

कोविड-19 और डिजिटल डिवाइड

कोविड-19 महामारी ने डिजिटल डिवाइड को और स्पष्ट कर दिया जिसे निम्नलिखित दो प्रमुख बिन्दुओं से समझा जा सकता है : क) शिक्षा पर प्रभाव- ऑनलाइन कक्षाओं के कारण लाखों छात्र शिक्षा से वंचित हो गए क्योंकि उनके पास इंटरनेट या उपकरण नहीं थे। ख) ग्रामीण छात्रों की चुनौतियाँ- नेटवर्क की समस्या एक मोबाइल पर कई बच्चों की पढ़ाई शिक्षकों की डिजिटल प्रशिक्षण की कमी इत्यादि ने डिजिटल डिवाइडदेविदे को गहराई से रेखांकित किया।

सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव

डिजिटल डिवाइड के अनेक सामाजिक प्रभाव भी हैं, जैसे- क) शिक्षा में असमानता- **बोर्दियो** के अनुसार- डिजिटल डिवाइड ने शिक्षा में वर्ग आधारित अंतर को और बढ़ा दिया है। ख) ई-गवर्नेंस में बाधाएँ- डिजिटल सेवाओं तक पहुँच न होने से नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं, विशेषकर बुजुर्ग और अशिक्षित लोगों के लिए यह एक गंभीर समस्या है। ग) सामाजिक स्तरीकरण- **कैसल्स** के अनुसार डिजिटल डिवाइड ने समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है: 1) डिजिटल एलाइट 2) डिजिटल अंडरक्लास। डिजिटल डिवाइड के अनेक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हैं, जैसे- तनाव और चिंता, शिक्षा से अलगाव इत्यादि। **हर्गिन्स** के अनुसार यह स्थिति डिजिटल बहिष्करण का स्पष्ट उदाहरण है।

समाधान

डिजिटल डिवाइड के प्रभावों को कम करने के लिए इसके समाधान स्वरूप नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जैसे- क) डिजिटल अवसंरचना का विस्तार- सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। ख) डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम- कमजोर वर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं। ग) सस्ती इंटरनेट सेवाएँ- डेटा की लागत को कम करना डिजिटल समावेशन के लिए आवश्यक है। घ) स्थानीय भाषाओं में सामग्री- भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल डिवाइड आधुनिक समाज की एक जटिल और बहुआयामी समस्या है। यह केवल तकनीकी असमानता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रश्न है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समाज दो वर्गों में विभाजित हो सकता है- डिजिटल रूप से सशक्त समाज और डिजिटल रूप से वंचित समाज। **वान डिज्क** कहते हैं कि डिजिटल समावेशन को नीति-निर्माण का प्रमुख हिस्सा बनाया जाए और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाएँ। डिजिटल डिवाइड आधुनिक समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को केवल विकास का साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी मानता है। डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच समाज

के विभिन्न वर्गों के बीच अवसरों की विषमता को बढ़ाती है जिससे सामाजिक न्याय और समावेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक समान रूप से योगदान करते हैं। उच्च आय वर्ग और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जहाँ डिजिटल तकनीकों का अधिक लाभ उठा पा रहे हैं वहीं ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग अभी भी बुनियादी डिजिटल सुविधाओं से वंचित हैं। यह असमानता केवल संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल साक्षरता और उपयोग कौशल की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। डिजिटल साक्षरता डिजिटल डिवाइड को कम करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। जिन व्यक्तियों को तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त है वे न केवल सूचना तक आसानी से पहुँच पाते हैं बल्कि उसे अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रभावी रूप से उपयोग भी कर सकते हैं। इसके विपरीत, तकनीकी ज्ञान के अभाव में व्यक्ति डिजिटल दुनिया से कट जाता है जिससे उसके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। लैंगिक असमानता भी डिजिटल डिवाइड का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई समाजों में महिलाओं की तकनीकी संसाधनों तक पहुँच सीमित होती है जिससे उनका डिजिटल सशक्तिकरण बाधित होता है। यह स्थिति उनके शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अतः डिजिटल समानता सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक दृष्टिकोण को विशेष महत्व देना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से, डिजिटल डिवाइड आय और रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित करता है। डिजिटल तकनीकों तक पहुँच रखने वाले व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं जबकि अन्य लोग इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार, डिजिटल असमानता आर्थिक असमानता को और गहरा करती है। अंततः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए समग्र और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करे, सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराए तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए। साथ ही, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास और महिलाओं एवं वंचित समुदायों को विशेष रूप से सशक्त बनाने के प्रयास भी आवश्यक हैं। इस प्रकार, डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना केवल तकनीकी विकास का प्रश्न नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ सूची (References)

- [1]. Castells, M. (2000), The rise of the network society, Blackwell Publishers, Oxford. pp. 24–28.
- [2]. Van Dijk, J. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society, Sage Publications, Thousand Oaks. pp. 201–218.
- [3]. Norris, P. (2001). Digital divide: Civic engagement, information poverty and the Internet worldwide, Cambridge University Press. Cambridge. pp. 38–48.
- [4]. Bourdieu, P. (1986), Handbook of theory and research for the sociology of education, Greenwood, New York, pp. 241–258.
- [5]. Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. First Monday, pp. 7.
- [6]. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). (2023). The Indian telecom services performance indicators report. Government of India.
- [7]. IMAI & Kantar. (2022). Internet in India report.

Cite this Article:

पाल, सन्तराम (2026). डिजिटल डिवाइड का समाजशास्त्रीय अध्ययन . *International Journal of Emerging Research in Arts, Science and Technology*, 1(5), 1–4.

Journal URL: <https://ijerast.com/> DOI: <https://doi.org/10.67715/ijerast.v1i5.29>

Disclaimer/Publisher's Note: The author(s) are solely responsible for the content and claims of this article. The publisher and editors assume no legal liability for any errors, copyright violations, or damages arising from its use.